

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019 के संबंध में नई दिल्ली में प्रस्तावित राज्यपाल सम्मेलन के एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा

कुलपतियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानक के  
अनुरूप हो – राज्यपाल

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा  
जाय – श्रीमती पटेल

लखनऊ : 18 सितम्बर, 2019

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज यहां राजभवन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019 के संबंध में नई दिल्ली में प्रस्तावित राज्यपाल सम्मेलन के एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा के लिये आयोजित बैठक में मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानक के अनुसार ही की जाय। उन्होंने नैक मूल्यांकन की स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसमें सुधार लाने के निर्देश दिये। उन्होंने नैक मूल्यांकन के संबंध में निर्देश दिये कि पांच-पांच विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ अलग-अलग समूह में बैठक आयोजित कर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया जाय, जिससे उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार आए। उन्होंने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने के निर्देश दिये। राज्यपाल ने आज की बैठक में प्रस्तावित राज्यपाल सम्मेलन के संबंध में दिये गये निर्देशों की विस्तृत रिपोर्ट आगामी 30 सितम्बर तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

अनुसंधान एवं नवाचार (Research and Innovation) के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा शिव नादर विश्वविद्यालय, नोएडा को Institution of Eminence घोषित किये जाने के संबंध में राज्यपाल ने निर्देश दिये कि उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी इस बात का अध्ययन कर पता लगायें कि इन दो विश्वविद्यालयों को श्रेष्ठ घोषित

किये जाने का आधार क्या है, जिससे राज्य विश्वविद्यालयों को उसी के अनुरूप शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिये दिशा-निर्देश दिया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित कर शोधार्थियों (Exceptional Performers) को विदेश भेजने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार करे।

फिट इण्डिया अभियान, उन्नत भारत अभियान, प्लास्टिक बैन अभियान आदि के संबंध में बैठक में विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्लास्टिक पर लगाये गये प्रतिबन्ध का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के साथ-साथ छात्रों में जागरूकता लाने के निर्देश दिये।

बैठक में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डा० दिनेश शर्मा के अलावा मुख्य सचिव श्री आर०के० तिवारी, अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, श्री हेमन्त राव, सचिव उच्च शिक्षा श्री आर० रमेश कुमार के साथ-साथ अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

ओ०पी० राय/दिलशाद/राजभवन (51/9)



